POSTAL REG.NO. RJ/JPC/M-28/2009-11 (RNI. REG. NO. 39658/83) # ग्रा.ग./2011/अंक 09

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 सितम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 सितम्बर, 2011 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम राम/सलाम! कुछ दिनों पहले उपभोक्ता आन्दोलन से जुड़ा हुआ मेरा एक चेला आया, जो किसी ग्राम पंचायत में सचिव की सेवा में है। उसकी कोशिश थी कि उसकी पोस्टिंग किसी 'कमाऊ' ग्राम पंचायत में लगाने की मैं सिफारिश करूँ। वो यह भी जानता था कि मैं ऐसी सिफारिश न करता हूँ और न ही करूँगा। पिछले 30 सालों में जनहित के मुद्दों पर काम करते हुए मैंने किसी भी तरह के भ्रष्ट कार्य से अपने आपको दूर रखा है, जिसका मुझे नुकसान भी हुआ है। लेकिन इस नीति से सिवाय संतुष्टि के मैंने समर्थन भी पाया है और सरकारी व्यवस्था में परिवर्तन लाने की शक्ति भी। बहरहाल, उस चेले का कहना था कि आज की प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार एक अभिन्न अंग बन गया है और ईमानदारों की कोई कद्र नहीं होती है। मैंने उसे विदा करते हुए सिर्फ यही कहा कि तुम पैसे खाओ कि नहीं, लेकिन जो भी काम करों तो दो बातों का ध्यान रखना। प्रथम, गरीबी उन्मूलन की योजनाओं का लाभ गरीबों को निश्चित रूप से मिले। द्वितीय, जो भी कार्य करो उसमें क्वालिटी से समझौता मत करना।

यह तो था हमारी प्रशासन व्यवस्था के धरातल का एक किस्सा। दूसरी तरफ बात है, हमारे देश में शीर्ष स्तर पर प्रधानमंत्री के आचारण की। कहते हैं डॉ. मनमोहन सिंह विश्व में सबसे अधिक पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं। उनके निजी आचरण पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह आचरण मंत्रीमंडल के हर सदस्य का भी होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आज की सरकार हमारे इतिहास में सबसे अधिक भ्रष्ट सरकार है। क्या डॉ. मनमोहन सिंह धृतराष्ट्र तो नहीं हैं?

आये दिन अखबार की सुर्खियों में कोई न कोई बड़े घोटाले की खबर छपती है। विश्व के 178 देशों में भ्रष्टाचार के मापदण्ड में भारत का नंबर 87वां है। भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा या तो चुनाव या उपभोग या विलासिता में उपयोग होता है। काफी पैसा तो वापिस हमारी अर्थव्यवस्था में आ जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि भारत से पलायन किया 21 लाख करोड़ रूपया बाहर के बैंकों में जमा है। इस रकम का सही अनुमान लगाए तो समझ ले कि यह धनराशि अगर भारत की 121 करोड़ जनता में बांटे तो हर एक नागरिक को 2000 रूपए हर महीने मिल जाएंगे व यह 60 साल तक खत्म नहीं होगा और देश से गरीबी का नाम ही मिट जाएगा।

बढ़ता हुआ भ्रष्टाचर एवं अनाचार से आप हम सब लोग उत्तेजित हैं। पिछले 65 वर्षों में हमने देखा है कि भ्रष्टाचार कहीं भी कम नहीं हुआ है, बल्कि भ्रष्टाचार 'अश्वमेघ घोड़े' का रूप ले चुका है। यह कुव्यवस्था शीर्ष स्तर से धरातल तक अपनी पैठ बना चुकी है। चाहे हथियार के सौदे हों या राशन कार्ड हो, बगैर घूस के काम ही नहीं हो पाता है। पूरे देश में 'कामधेनू' पदों की नीलामी होती है और जो इन पदों को खरीदता है वह फिर येनकेन प्रकारेण उस दाम का चार गुना या उससे अधिक वसूल करता है।

इन सभी बातों को लेकर अन्ना हजारे ने बिगुल बजाया है और पूरे देश में अलख जगाई है। आइयें, हम सब इस आजादी के दूसरे आन्दोलन में भाग लें।

बुना हुआ है भ्रष्टाचार का जाल

श्री राजीव गांधी यदि आज जिन्दा होते तो वह यह जान कर काफी खुश होते कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में उनके द्वारा कही गई सच्चाई में कितना दम था। उनका कहना था कि इस प्रणाली के जरिए वास्तविक हकदारों तक सिर्फ 10 फीसदी हिस्सा ही पहुंच पाता है। उनकी इस बात की पुष्टि पिछले दिनों शिखा झा और भरत रामास्वामी द्वारा किए गए शोध में हुई है।

शोध में बताया गया है कि इस प्रणाली का मध्यम वर्ग उनसे लगभग दोगुना फायदा उठाता है। करीब 43 फीसदी हिस्से का अवैध तरीकों से गबन कर दिया जाता है। लगभग 28 फीसदी हिस्सा खाद्य निगम व सरकारी ढांचे द्वारा जरूरत से ज्यादा लागत के रूप में खर्च कर दिया जाता है। इन सब बातों के मद्देनजर, लाख टके का सवाल यह है कि क्या इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारा जा सकता है, जो कि लगभग असम्भव कार्य नजर आता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति डी.पी.बधवा की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अध्ययन हेतु गठित समिति की रिपोर्ट के सिहांवलोकन अध्याय में न्यायमूर्ति बधवा लिखते हैं 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है... इस प्रणाली के चारों ओर राजनेताओं, नौकरशाहों, ट्रान्सपोर्टरों तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार का जाल बुना हुआ है। इन बेशर्म लोगों को गरीबों को उनके भोजन से वंचित करने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं है।'

बढ़ती जा रही है भ्रष्टाचार की समस्या

देश में व्याप्त भ्रष्टाचार से लगभग सभी भारतीय हताश हो चुके हैं। भ्रष्टाचार की समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। अमरीकी सर्वेक्षण एजेंसी 'गैलप' के अनुसार 2010 में करीब आधे लोगों ने माना कि पांच साल पहले की तुलना में भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ा है जब कि 27 फीसदी लोगों ने इसे समान ही बताया है।

सर्वेक्षण के अनुसार, भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की लड़ाई को मिले व्यापक जनसमर्थन व भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनों से जाहिर होता है कि भारतीयों ने मान लिया है कि भ्रष्टाचार की समस्या समाज में गहराई से पैठ कर गई है। सरकार भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सर्वेक्षण में 6000 लोगों को शामिल किया गया।

भ्रष्टाचार के शर्मनाक आंकड़े

- *78 फीसदी भारतीयों ने माना सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त*
- *71 फीसदी ने कहा व्यापार में भी भ्रष्टाचार*
- *65 फीसदी बेरोजगारों को देनी पड़ी घूस*
- *पांच में से एक व्यक्ति ने कहा कि बीते एक साल में उन्हें देनी पड़ी रिश्वत*

राजस्थान भी अव्वल

महाराष्ट्र व राजस्थान जैसे बड़े राज्य भ्रष्टाचार की सीढ़ी में शीर्ष पायदान पर खड़े हैं। इन राज्यों में दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या के मुकाबले दोषियों को सजा दिए जाने का प्रतिशत भी काफी कम है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2000 से 2009 के बीच महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के कुल 4566 मामले दर्ज किए गए। उनमें से केवल 27 फीसदी ही दोषी साबित हो पाए।

इसी प्रकार राजस्थान में दर्ज 3770 मामलों में से 33 फीसदी मामलों का ही निपटारा हो पाया। वर्ष 2000 में कुल 2943 मामले दर्ज हुए, वहीं 2009 में 3683 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए।

माथे पर लगा है कंलक

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश में भ्रष्टाचार से हर व्यक्ति पीड़ित है। लोगों के मानवीय मूल्य बदल गए हैं। लोग रातों रात लखपति और करोड़पति बन जाना चाहते हैं। आज राजनेता भ्रष्टाचार की कालिख से पोत दिए गए है। लेकिन वास्तविक सच्चाई यह है कि कुछ ही भ्रष्टाचारियों की वजह से यह कलंक सभी के माथे पर लगता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मूल्यों में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें समाज के बुद्धिजीवियों की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वे समाज को सही मूल्यों की शिक्षा दें।

चुनाव है सबसे बड़ा स्त्रोत

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई.कुरेशी ने कहा है कि चुनाव भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्त्रोत है और चुनावों के दौरान देश में पेड न्यूज की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हाल ही पेड न्यूज के 86 मामले हमारे नोटिस में आए हैं। उन्होंने कहा मीडिया घरानों और राजनीतिक दलों के बीच की संधियां परेशान करने वाली हैं।

पहले यह सांकेतिक विज्ञापन होता था, लेकिन अब राजनीतिक दल और मीडिया घराने ज्यादा साहसी हो गए हैं और चुनावी घोषणा-पत्र को संपादकीय के रूप में छाप रहे हैं। यह सिर्फ अनैतिक ही नहीं बल्कि तकलीफ दायक भी है।

चन्दा है असली जड़

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं द्वारा लिया जाने वाला चन्दा ही भ्रष्टाचार की जड़ है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि अब चुनाव के लिए उद्योगपतियों, औद्योगिक घरानों व गलत कमाई करने वाले लोगों से चन्दा लेने के बजाय 'स्टेट फंड्रिग' पर विचार करे।

नियंत्रक व लेखा परीक्षक 'केग' के 150वें वर्ष समारोह में यह विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के मकसद से लाया गया है, यह आम आदमी का हथियार बने।

घिर गई केन्द्र सरकार

केन्द्र की यूपीए सरकार घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। जनता के सामने 2जी स्पेक्ट्रम, कामनवेल्थ, आदर्श हाउसिंग, गैस बेसिन और अनाज जैसे कई घोटाले सामने आ रहे हैं।

इनमें उच्च स्तर पर अरबों-खरबों रुपए की अनियमितता और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ हैं। मामलों की जांच में अन्य कई राज नेता भी चपेट में आते जा रहे हैं।

केन्द्र सरकार सिर्फ अपने बचाव में लगी है। आर्थिक और नीतिगत फैसले टाले जा रहे हैं। जन हित की घोषणाओं और विकास योजनाओं पर ब्रेक लगा है। पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम का मानना है कि सरकार कुछ हद तक पंगू है। भ्रष्टाचार से हमारी आर्थिक प्रगति को काफी नुकसान हुआ है।

देश को हुआ नुकसान

देश के आजाद होने के बाद से वर्ष 2008 तक भ्रष्टाचार, कर चोरी और अपराध के जरिए 21 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। काले धन पर शोध और सलाह देने वाली एक अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है।

शोध से पता चला है कि समय समय पर गलत तरीके से लेन-देन के कारण भारत को करीब 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसका मौजुदा मूल्य 21 लाख करोड़ रुपए है।

ग्लोबल फाइनेंशियल इंटिग्रिटी संस्था की रिपोर्ट यह भी है कि 1991 के बाद भारत ने तेजी से आर्थिक प्रगति की है। ज्यादा कमाई होने से उतनी ही तेजी से काला धन बढ़ा है। काले धन के अत्यधिक जमाव से देश में गरीब और अमीर के बीच का फासला बढ़ा है। विदेशी बैंकों में निजी क्षेत्र की जमा पूंजी जो वर्ष 1991 में 36.4 प्रतिशत थी वह 2009 में 54.2 प्रतिशत पहुंच गई है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ बना माहौल

पिछले साल के अन्त में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार और घोटालों के एक के बाद एक मामले खुलकर सामने आए। इससे जनमानस जागा और माहौल भ्रष्टाचार के खिलाफ बनने लगा।

विभिन्न वेबसाइट्स पर रोज हजारों की संख्या में लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने विचार दर्ज करा रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक सरकार के अंदर बदलाव नहीं आएगा।

आरटीआई कार्यकर्ता अरविन्द केजरीवाल कहते हैं कि इंटरनेट पर आ रही शिकायतें बता रही हैं कि लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। सरकार इस बात से जरूर डर रही है कि यह गुस्सा सार्वजनिक आंदोलन न बन जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ अदालतों का सख्त रुख सरकार और जांच एजेंसियों पर लगाम कसने में मददगार हो रहा है।

आपकी चिट्ठी मिली

हर बार की तरह 'ग्राम गदर' का अगस्त, 2011 का अंक इस बार भी प्राप्त हुआ। मेरा विचार है, मंदिर हिन्दु समाज के लिए धर्मार्थ स्थान है। मंदिर जाने से मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी मंदिर वातावरण में अपने आप को आनन्दित और सुखी अनुभव करते हैं। नियमित रूप से मंदिर जाने वाले लोगों में बिना किसी छोटे-बड़े के भेदभाव के आपसी व्यवहार बन जाता है और उनमें आपसी बात-चीत के माध्यम से विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करने का मौका मिलता है। इससे विचारशीलता और ज्ञान में वृद्धि होती है।

आज के भौतिकतावादी परिप्रेक्ष और गिरते समाज के स्तर में ईश्वर की प्रार्थना व याचना करने पर शांति और सुख का अनुभव होता है। इसके अलावा मन्दिरों से अनेक लोगों को रोजगार भी मिलता है यथा फूलमाला, प्रसाद-सामग्री बेचने व पूजा-पाठ कराने वाले आदि।

जहां तक छुआछूत का सवाल है मेरे खयाल से यह काफी हद तक खत्म हो चुका है। यह हिन्दु समाज में प्राचीन वर्ण व्यवस्था की देन है। जैसे-जैसे समय बीतेगा वैसै-वैसे यह समाप्त होती जाएगी इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है।

- किशोर रूंगटा, जयपुर

माह अगस्त, 2011 का 'ग्राम गदर' का अंक 'दलित विशेषांक' के रूप में पढ़ने को मिला। इस बारे में जानकारी प्रकाशित कर उसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए अनन्त आभार! दलितों के अत्याचार निवारण के लिए कठोर कानून बने हैं। वर्षों से दलित वर्ग के साथ भेदभाव, ऊंचनीच और छुआछूत का आचरण होता रहा है।

वास्तविकता यह भी है कि भेदभाव किया जाना सिखाया भी, बताया भी जाता रहा है। परिणाम स्वरूप इसकी जडें बहुत गहरी हो गई। जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था जैसे देश का आधार हो गया हो ऐसा रहा। इसके परिणामस्वरूप ऊंचनीच में बदलता चला गया। कोई भी प्राणी किसी भी प्राणी से भेदभाव, ऊंचनीच का व्यवहार करे और अपने को धर्मी होना दर्शाये यह कैसी धार्मिकता और मानवता है? अंक के लिए आभार!

- मदन सालवी 'ओजस्वी'
कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़

मुश्किल होता जाएगा भ्रष्टाचार को रोकना

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के भ्रष्टतम देशों में शामिल है। सम्पूर्ण भारतीय समाज नित नए हो रहे घोटालों से त्रस्त हैं। कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.एम.शर्मा लिखते हैं कि आज समाज, राजनीति और शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार, अनाचार, अनैतिकता, और असंवेदनशीलता इतनी बढ़ गई है कि उस पर प्रभावी रोकथाम के लिए एक शक्तिशाली निकाय की आवश्यकता है।

खेद यह है कि हमारी संसद और संसद के बाहर लोकपाल और लोकायुक्त नाम के निकाय स्थापित करने को लेकर पिछले चार दशकों से विचार विमर्श तो हो रहा है। लेकिन आज तक भारतीय शासन यह निर्णय नहीं कर पाया कि देश में शिखर स्तर पर लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्था हो या नहीं?

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा विकास का पैसा

'विकास के लिए मिलने वाला ज्यादा पैसा निरर्थक जाने की प्रमुख वजह भ्रष्टाचार है। इससे आर्थिक और सामाजिक विषमता है। जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हमारे विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है।'

- प्रतिभा पाटील, राष्ट्रपति

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट **राजकुमार त्रिवेदी,** 'कट्स' जयपुर